मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1266

28.07.2025 को उत्तर के लिए

झारखंड के लिए समर्पित जलवायु बजट

1266. श्री नलिन सोरेन:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को झारखंड राज्य सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तैयार किए गए समर्पित जलवायु बजट की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के प्रभावों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पिछले बजट के अनुरूप झारखंड राज्य का जलवायु प्रतिक्रिया एजेंडा निर्धारित किया है और जलवायु संबंधी सार्वजनिक व्यय की अधिक प्रभावशीलता के साथ-साथ जलवायु अनुकूलन और शमन को प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) की रणनीति के अनुसार उक्त राज्य में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और पिछले दो वर्षों के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि उपयोग की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग): भारत की जलवायु संबंधी कार्रवाइयां विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं और इन्हें झारखंड सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में (एनएपीसीसी) जलवायु से संबंधित कार्यकलापों के लिए व्यापक रूपरेखा दी गई है और इसमें सौर ऊर्जा, संवर्धित ऊर्जा दक्षता, संधारणीय पर्यावास, जल, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की संधारणीयता, हरित भारत, संधारणीय कृषि, मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के मिशन शामिल हैं। इन सभी मिशनों को उनके संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा संस्थागत रूप दिया गया है और कार्यान्वित किया गया है, जिसमें उनके वार्षिक बजटीय आवंटनों के एक भाग के रूप में उनकी संगत योजनाओं के अंतर्गत धन का आवंटन करना भी शामिल है।

झारखंड ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) और मिशन लाइफ के अनुरूप जलवायु एजेंडा निर्धारित किया है। सार्वजनिक निवेश को सुगम बनाने के लिए, सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना, झारखंड जलछाजन योजना और इसी तरह की अन्य योजनाओं के माध्यम से आय सृजन के साथ-साथ हरित आवरण को बढ़ावा देने जैसे कदम उठाए हैं। ये योजनाएँ आय सृजन के माध्यम से अनुकूलन और हरित आवरण में वृद्धि के माध्यम से उपशमन में मदद कर रही हैं। इसके अलावा, झारखंड ने केंद्र सरकार के सहयोग से जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) तैयार कर प्रस्तुत कर दी है।

यह राज्य 'जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसकेसीसी)' के तहत एक परियोजना पर भी काम कर रहा है, जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के तहत नौ मिशनों में से एक है, जिसके माध्यम से अनुसंधान और अध्ययन और समुदायों के क्षमता निर्माण पर 58.61 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

*****